एनओसी के लिए निवेशक अब नहीं होंगे परेशान

वार्षिक लक्ष्य निर्धारण को लेकर इन्वेस्ट यूपी की बैठक, एनओसी दिलाने में मदद करेंगे उद्यमी मित्र

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश करने वाले निवेशकों को अब विभिन्न प्रकार की एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेने के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिलों में तैनात उद्यमी मित्र निवेशकों को एनओसी दिलाने से लेकर भूमि आवंटन में मदद करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने उद्यमी मित्रों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने व लंबित प्रस्तावों का एक माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपये निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में करीब 2.77 लाख करोड़ रुपये का ही निवेश हो सका है। इसलिए इन्वेस्ट यूपी ने चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य निर्धारण को लेकर सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समीक्षा बैठक आयोजित की। मंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, हाथरस, कानपुर नगर व प्रतापगढ़ में निवेश के लंबित प्रस्तावों के बारे में संबंधित जिलों के उद्यमी मित्रों से जानकारी हासिल की।

उद्यमी मित्र मंत्री के प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे सके। वर्तमान में निवेश मित्र पोर्टल पर 700 से अधिक प्रस्ताव लंबित हैं। इसे लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निवेशकों से फीडबैक लेकर हर माह इन्वेस्ट यूपी की तरफ से समीक्षा बैठक की जाए।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोमवार को इन्वेस्ट यूपी की वार्षिक लक्ष्य निर्धारण की समीक्षा बैठक के दौरान औद्योगिक मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी, इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार व अन्य ● जागरण

निवेश बढ़ाने के लिए हर माह होगी बैठक, निवेशकों से फीडबैक लेगा इन्वेस्ट यूपी

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा निवेश के लिए भूमि बैंक बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए बंद कारखानों की भूमि चिह्नित कर वहां निवेश कराया जा सकता है। हाल ही में प्रदेश की बंद बड़ी टेक्सटाइल मिलों की भूमि को चिह्नित करके वहां पर टेक्सटाइल पार्क खोलने की योजना पर काम शुरू किया गया है। मुख्य सचिव ने उद्योगों को भूमि आवंटित जाने की प्रक्रिया को सरल करने का सुझाव दिया। कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चार अधिकारियों की समिति गठित की जाए।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि 30 हजार एकड़ का भूमि बैंक होने के बाद भी निवेशकों को भूमि आवंटन के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भूमि आवंटन से लेकर सब्सिडी के लिए निवेशकों को विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि आज से चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर उद्यमी मित्र पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सूर्य पाल गंगवार, इनवेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रथमेश कुमार ने भी अपने सुझाव दिए। समीक्षा बैठक में आए सुझावों के आधार पर निवेश मित्र पोर्टल 3.0 को और विकसित किया जाएगा।